भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 545
उत्तर देने की तारीख 03 दिसंबर, 2025

दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र

545. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देशभर में समान डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ): जी हां, सरकार ने देश में दूरसंचार सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं जिससे दूरसंचार सेक्टर का विकास हुआ है। इन उपायों में समायोजित सकल राजस्व का युक्तिकरण; बैंक गारंटी (बीजी) का युक्तिकरण; ब्याज दरों का युक्तिकरण और जुर्मानों को हटाना; किस्त भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए बीजी (दिनांक 15.09.2021 के बाद आयोजित नीलामियों के लिए) आवश्यकता को समाप्त करना; 10 वर्षों के बाद स्पेक्ट्रम सरेंडर की अनुमति (आगामी नीलामियों में); दिनांक 15.09.2021 के बाद आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामियों के तहत प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) की आवश्यकता को समाप्त करना; स्पेक्ट्रम साझा करने के लिए 0.5% अतिरिक्त एसयूसी को हटाना; सुरक्षा उपायों के अध्यधीन

स्वचालित मार्ग के तहत दूरसंचार सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति; बेतार उपकरणों के लिए 1953 की सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत लाइसेंस की आवश्यकता को स्व घोषणा में परिवर्तित करना; पेपर कस्टमर ऐक्विज़िश्न् फॉर्म्स को डिजिटल डाटा स्टोरेज से प्रतिस्थापित करना; दूरसंचार टावरों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए) की मंजूरी को सरल बनाना तथा स्पेक्ट्रम की अवधि को बढ़ाकर 20 से 30 वर्ष तक करना।

इससे पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल अवसंरचना में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क मार्च 2018 में 17.5 लाख किलोमीटर से बढ़कर सितंबर 2025 में 42.36 लाख किलोमीटर हो गया है, जबकि बेस ट्रांसीवर स्टेशनों की संख्या मार्च 2018 में 17.3 लाख से बढ़कर अक्टूबर 2025 में 31.4 लाख हो गई है। अक्टूबर 2025 तक, भारत के 6,44,131 गाँवों में से 6,34,019 गाँव मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर हैं, जिनमें से 6,30,676 गांवों में 4जी सेवाएँ हैं। ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन सितंबर 2018 में 48 करोड़ से बढ़कर जून 2025 में 98 करोड़ हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, 31 अक्टूबर 2025 तक देश भर में 3.80 लाख पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट संस्थापित किए जा चुके हैं। डेटा खपत में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो सितंबर 2018 में प्रति ग्राहक प्रति माह 8.32 जीबी से बढ़कर सितंबर 2025 में प्रति ग्राहक प्रति माह 25.24 जीबी हो गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान औसत वायरलेस डेटा टैरिफ प्रति जीबी ₹10.91 से घटकर ₹8.27 हो गया है।

इसके अलावा, देश भर में समान डिजिटल एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए सरकार डिजिटल भारत निधि के तहत विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है, जैसे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए 4जी सेचुरेशन परियोजनाएँ और संशोधित भारतनेट कार्यक्रम।

***